भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4947
1 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र में कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन

4947 # श्री राजमोहन उन्नीथन :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के इस्पात क्षेत्र में कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) देश में इस्पात निर्माण में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल के इस्पात क्षेत्र को इसकी उत्सर्जन तीव्रता को कम करने में सहायता के लिए क्या विशिष्ट सहायता प्रदान की जा रही है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): इस्पात निर्माण में नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन सहित भारत के इस्पात क्षेत्र में सीओ2 उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :

i. मंत्रालय ने कम उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित करने और श्रेणीबद्ध करने हेतु मानक प्रदान करने हेतु हरित इस्पात के लिए वर्गीकरण जारी किया है।
ii. इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के अनुरूप ''ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया : रोडमैप एंड एक्शन प्लान'' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो 2070 तक निवल-शून्य लक्ष्यों की ओर ग्रीन स्टील और संधारणीयता के लिए भावी रोडमैप प्रदान करती है। यह रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
iii. इस्पात मंत्रालय ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग हेतु पॉयलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 07 पॉयलट परियोजनाएं प्रदान की हैं।
iv. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

इस्पात क्षेत्र से उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने के लिए उठाए गए उपर्युक्त उपायों को केरला के लिए भी जारी किया गया है।

*****